



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 207]
No. 207]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 25, 2003/भाद्र 3, 1925
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 25, 2003/BHADRA 3, 1925

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2003

अंतिम निष्कर्ष

विषय : चीन जनवादी गणराज्य मूल के अथवा वहां से निर्यातित पैरा क्रेसोल के आयात के सम्बन्ध में पाटनरोधी जांच।

सं. 14/29/2002-डीजीएडी.— वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आंकलन एवं संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 को ध्यान में रखते हुए:

क. प्रक्रिया

2. जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है:-

- (i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) को उपर्युक्त नियमों के अंतर्गत घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले मै0 अतुल लि0, गुजरात से एक लिखित याचिका प्राप्त हुई है जिसमें चीन जनवादी गणराज्य (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए पैरा क्रेसोल (जिसे इसके बाद संबद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया गया है :

(ii) आवेदन की प्रारंभिक जांच से कतिपय त्रुटियों का पता लगा जिन्हें याचिकाकर्ता द्वारा बाद में ठीक कर दिया गया था। इसके बाद याचिका को समुचित ढंग से प्रलेखित माना गया था:

(iii) प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के उपनियम(5) के अनुसार जांच शुरू करने की कार्यवाही से पहले याचिकाकर्ता द्वारा पाटन के बारे में दिए गए आवेदन के संबंध में भारत में स्थित चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास को अधिसूचित किया :

(iv) प्राधिकारी ने 27 अगस्त, 2002 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया जिसके द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची-I के अध्याय शीर्ष/उपशीर्ष 2907.12 में शामिल पैरा क्रेसोल के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की कार्यवाई शुरू की।

(v) प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की एक प्रति सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और शिकायतकर्ताओं को भेजी और उन्हें अपने-अपने विचारों से लिखित रूप में अवगत कराने का अवसर प्रदान किया।

(vi) प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 6 के उप-नियम (3) के अनुसार याचिका की एक प्रति सभी ज्ञात निर्यातकों तथा भारत में सम्बद्ध देश के दूतावास को भेजी।

(vii) संबद्ध माल के आयात-ब्यौरे उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) से अनुरोध किया गया :

(viii) जांच आरंभ किए जाने के बारे में नियम 6(2) के अनुसार संबद्ध देश के दूतावास को सूचना दी गई और उनसे अनुरोध किया गया कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को यह सलाह दे दें कि वे प्रश्नावली का निर्धारित समयावधि के भीतर प्रत्युत्तर भेज दें। उन्हें निर्यातकों भेजे गए पत्र, याचिका तथा प्रश्नावली की एक प्रति भी भेजी गई :

(ix) संबद्ध माल के भारत के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं (प्रारंभिक निष्कर्षों में दिए गए ब्यौरे के अनुसार) प्रश्नावली भेजी गई और नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक जानकारी मांगी गई :

(x) याचिकाकर्त्ताओं से क्षति के संबंध में अतिरिक्त जानकारी मांगी गई जिसे प्राप्त कर लिया गया ।

(xi) कुछ इच्छुक पक्षकारों ने प्रश्नावली का प्रत्युत्तर देने हेतु समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया जिसे प्रस्तुत कारण के आधार पर स्वीकृत किया गया ।

(xii) प्राधिकारी ने दिनांक 17 जनवरी, 2003 की अधिसूचना द्वारा प्रारंभिक निष्कर्षों को अधिसूचित किया और इच्छुक पक्षकारों से अनुरोध किया कि वे इसके प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों के भीतर अपने-अपने विचार लिखित रूप में उपलब्ध करा दें:

(xiii) प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के दूतावासों को भी प्रारंभिक निष्कर्षों की एक-एक प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे संबद्ध माल के निर्यातकों/उत्पादकों और अन्य पक्षकारों को यह सलाह दे दें कि वे प्रारंभिक निष्कर्षों पर अपने-अपने विचार उपर्युक्त निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत कर दें :

(xiv) प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षों की एक-एक प्रति सभी ज्ञात निर्यातकों (जिनके ब्यौरे याचिकाकर्त्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए थे), अन्य निर्यातकों जिन्होंने जांच-प्रारंभ अधिसूचना का प्रत्युत्तर दिया, भारत के आयातकों को प्रेषित की और उनसे अनुरोध किया गया कि वे प्रारंभिक निष्कर्षों पर अपने-अपने विचार, यदि कोई हों, पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर प्रस्तुत कर दें:

(xv) प्राधिकारी ने इच्छुक पक्षकारों को इस बात का अवसर प्रदान किया कि वे दिनांक 23 अप्रैल, 2003 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप में अपने-अपने विचार प्रस्तुत करें । अपने-अपने विचार प्रस्तुत कर रहे सभी पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे अपने अपने प्रस्तुत विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत कर दें । इन पक्षकारों को सलाह दी गई थी कि वे विरोधी पक्षकारों द्वारा व्यक्त विचारों की प्रतियां एकत्र करें और उनका खंडन, यदि कोई हो, करें:

(xvi) प्राधिकारी ने सभी इच्छुक पक्षकारों को नियम 6(7) के अनुसार अनुरोध पर निरीक्षण हेतु वह सार्वजनिक फाइल उपलब्ध कराई जिसमें विभिन्न इच्छुक पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय हिस्सा शामिल था :

(xvii) प्रारंभिक निष्कर्षों की घोषणा से पहले इच्छुक पक्षकारों द्वारा दी गई दलीलों की, जिन्हें प्रारंभिक निष्कर्षों में शामिल किया गया था, संक्षिप्तता के प्रयोजनार्थ यहां पुनरावृत्ति नहीं की गई है। तथापि, बाद में इच्छुक पक्षकारों द्वारा दी गई दलीलों को प्रकटीकरण विवरण-पत्र तथा इन निष्कर्षों में समुचित रूप से शामिल किया गया है :

(xviii) उपर्युक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार इन निष्कर्षों के लिए आवश्यक तथ्यों/आधार को एक प्रकटीकरण विवरण-पत्र द्वारा दिनांक 8 अगस्त, 2003 को ज्ञात इच्छुक पक्षकारों को बता दिया गया और उस पर प्राप्त टिप्पणियों को इन निष्कर्षों में शामिल किया गया है:

(xix) घरेलू उद्योग की मौके पर पड़ताल (जैसा कि आवश्यक समझा गया) सहित लागत जांच भी की गई ताकि अनुकूल उत्पादन-लागत तथा सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) और याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर संबद्ध माल के विनिर्माण तथा बिक्री की लागत का आकलन किया जा सके :

(xx) इस अधिसूचना में *** पर वह जानकारी है जो गोपनीय आधार पर इच्छुक पक्षकारों द्वारा दी गई है और प्राधिकारी ने नियमावली के तहत इस पर विचार किया है:

(xxi) जांच में दिनांक 1 अप्रैल, 2001 से दिनांक 21 मार्च, 2002 तक की अवधि शामिल है।

(xxii) प्रारंभ सूचना तथा प्रारंभिक निष्कर्षों की प्रतियां फिक्की, सी आई आई, एसोचैम, आदि को भी व्यापक परिचालन हेतु भेजी गई।

ख. याचिकाकर्ताओं, निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य इच्छुक पक्षकारों के विचार और प्राधिकारी द्वारा जांच:

3. विभिन्न इच्छुक पक्षकारों द्वारा व्यक्त विचारों की चर्चा प्रारंभिक निष्कर्षों तथा प्रकटन विवरण-पत्र में की गई है, जिन विचारों की चर्चा पहले प्रारंभिक निष्कर्षों और प्रकटन विवरण-पत्र में नहीं की गई है और जिन्हें प्रकटन विवरण-पत्र के प्रत्युत्तर में उठाया गया है उन्हें नियमानुसार यथावांछित सीमा तक तथा इस मामले के संबंध के अनुसार अगले संगत पैराग्राफों में प्रस्तुत किया गया है। इच्छुक पक्षकारों द्वारा दी

गई गई दलीलों की जांच की गई, उन पर विचार किया गया और यथावश्यकतानुसार उन पर नीचे पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

4. प्रारंभिक निष्कर्षों के स्तर पर निम्नलिखित से उत्तर प्राप्त हुए थे:-

निर्यातक

- (i) मैसर्स नानजिंग लांग्यान कैमिकल कं० लि०, चीन
- (ii) मैसर्स नानजिंग जिगमाई कैमिकल कं० लि०, चीन
- (iii) ब्लैक रोज एक्सपोर्ट्स प्रा० लि०, मुंबई

आयातक

- (i) मै० नंदोलिया आर्गेनिक कैमिकल प्रा० लि०, मुंबई
- (ii) मै० यूनिवर्सल कैमिकल एण्ड इंडस्ट्रीज लि०, मुंबई
- (iii) मै० ब्लैक रोज एक्सपोर्ट्स प्रा० लि०, मुंबई
- (iv) ग्लोबल बल्क ड्रग्स एंड फाइन केमिकल प्रा० लि०, हैदराबाद
- (v) अनंत फ्रेग्रेंस प्रा० लि०
- (vi) सौर्या ग्लोबल प्रा० लि०, मुंबई
- (vii) जेनिथ इंटरप्राइजेस, अहमदाबाद
- (viii) नायकनवारे केमिकल्स लि०, मुंबई

विभिन्न इच्छुक पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों का जिक्र प्रारंभिक निष्कर्षों में कर दिया गया है अतः सक्षिप्तता के प्रयोजनार्थ उनकी पुनरावृत्ति यहां नहीं की जा रही है। सार्वजनिक सुनवाई तथा प्रकटन विवरण-पत्र के बाद केवल निम्नलिखित आयातकों ने दलील प्रस्तुत की है जिसकी इन निष्कर्षों में समुचित रूप से चर्चा की गई है:-

- (i) मै० ब्लैकरोज एक्सपोर्ट्स प्रा० लि०
- (ii) मेट्रोकेम इंडस्ट्रीज लि०,
- (iii) नन्दोलिया आर्गेनिक केमिकल्स प्रा० लि०
- (iv) यूनिवर्सल केमिकल इंडस्ट्रीज लि०, और

(v) इन्वेंटा केमिकल लि०

(vi) पारा क्रेसोल कंजूमर्स एसोसिएशन, मुंबई

5. विचाराधीन उत्पाद

इस जांच में विचाराधीन उत्पाद पैरा क्रेसोल है । इस उत्पाद में रंजकों, पिगमेंट्स, सुगंध तथा ड्रग मध्यवर्ती सामान, ऑप्टिकल ब्राइटनर, सर्फैक्टेंट्स, सिंथेटिक खाद्य स्वाद, अल्ट्रा वाचलेट लाइट ऐब्जाबर्बर, ऐंटी-आक्सिडेंट्स तथा लुब्रिकेंट्स के लिए स्टेबिलाइजर्स के प्रमुख प्रयोग शामिल हैं ।

एक आयातक ने यह दलील दी है कि याचिकाकर्ता द्वारा 99% से अधिक की शुद्धता वाले पैराक्रेसोल की बाजार में आफर नहीं की गई है । अतः 99% शुद्धता वाले पैरा क्रेसोल को मौजूदा याचिका के दायरे से हटा दिए जाने की जरूरत है । घरेलू उद्योग ने अपने लिखित निवेदनों में यह पुष्टि की है कि वे 99% तक की शुद्धता वाले पैरा क्रेसोल के सभी ग्रेडों का विनिर्माण करते हैं । इसके आलावा, 99% से अधिक के पैरा क्रेसोल की बाजार में आफर नहीं की जाती है । प्रकटन विवरण-पत्र के प्रत्युत्तर में आयातकों की यह दलील है कि याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि वे 99% शुद्धता वाले पैरा क्रेसोल की आफर नहीं करते हैं । मामला ऐसा नहीं क्योंकि घरेलू उद्योग ने सार्वजनिक सुनवाई के बाद अपने लिखित निवेदन में पुष्टि कर दी थी कि वे 99% तक की शुद्धता युक्त पैरा क्रेसोल के सभी ग्रेडों का विनिर्माण करते हैं । इस प्रकार आयात की दलील सही प्रतीत नहीं होती है । प्राधिकारी का विचार यह है कि 99% शुद्धता वाले माल को जांच के दायरे से हटा दिए जाने संबंधी दलील निश्चायक नहीं है तथा इसके लिए पर्याप्त औचित्य नहीं दिया गया है । प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद संबंधी प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि करता है ।

6. समान वस्तु:

याचिकाकर्ताओं का दावा है कि भारत में घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पादों और आयातित उत्पादों के बीच कोई अंतर नहीं है, प्रारंभिक निष्कर्षों के संबंध में प्राधिकारी का निर्णय है कि कि घरेलू उद्योग में उत्पादित पैरा क्रेसोल विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है । समान वस्तु के मुद्दे पर प्रारंभिक निष्कर्षों के बाद कोई पर्याप्त दलील प्राप्त नहीं हुई है । अतः प्राधिकारी समान वस्तु के संबंध में प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि करता है ।

7. घरेलू उद्योग

घरेलू उद्योग के मुद्दे पर प्राधिकारी प्रारंभिक निष्कर्षों का स्मरण करता है। याचिका मै0 अतुल लि0 (एरोमेटिक्स डिवीजन), जिला वनसड, गुजरात द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता कंपनी भारत में पैराक्रैसोल का एक मात्र उत्पादक है। अतः उनका उत्पादन संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादन का 100% बनता है। याचिकाकर्ता ने सूचित किया है कि उन्होंने निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए अग्रिम लाइसेंस के तहत जांच अवधि के दौरान 32 मी. टन पैरा क्रैसोल का आयात किया है। कुछ आयातकों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता ने जांच अवधि के दौरान आयात किया है, इसलिए, उन्हें पात्र घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना जाए। प्राधिकारी ने नोट किया था कि मै0 अतुल लि0 द्वारा जांच अवधि के दौरान 32 मी. टन का जो आयात किया गया था वह निर्यात उत्पादन के लिए था और यह आयात उनके पैराक्रैसोल के संयंत्र को सुनियोजित ढंग से बंद किए जाने के कारण आवश्यक था। प्राधिकारी यह नहीं समझता है कि निर्यात उत्पादन हेतु आयात की इस अल्प मात्रा से याचिकाकर्ता उपर्युक्त नियम 2(ख) के अर्थ के अन्तर्गत "घरेलू उद्योग" के रूप में माने जाने के लिए अपात्र बन जाता है। अतः याचिकाकर्ता को घरेलू उद्योग का प्रतिनिधि समझा गया।

आयातकों अर्थात् मै0 ब्लैकरोज एक्सपोत्स प्रा0 लि0, मेट्रोकेम इण्डस्ट्रीज लि0, नन्दोलिया आर्गेनिक केमिकल्स प्रा0 लि0 और यूनिवर्सल केमिकल्स इण्डस्ट्रीज लि0 की ओर से यह कहते हुए दलील दी गई है कि याचिकाकर्ता को याचिका दायर करने की प्रतिष्ठा नहीं है क्योंकि उन्होंने संबद्ध माल का आयात किया है। इसके अलावा, यह दलील दी गई है कि प्राधिकारी द्वारा मै0 अतुल लि0 को घरेलू उद्योग मामले में आघात निम्नलिखित तीन कारण पर्याप्त नहीं हैं:-

- (i) याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आयात अपर्याप्त है :
- (ii) आयात अग्रिम लाइसेंस के तहत किए गए:
- (iii) आयात ऐसे समय पर किए गए जब उत्पाद सुविधाएं अस्थायी रूप से बंद थीं।

यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आयातों का हिस्सा आयातों का 5% से भी अधिक रहा जबकि डब्ल्यूटीओ के तहत आयात मात्रा का 3% काफी समझा जाता है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता द्वारा किए गए ये आयात इस उत्पाद की मांग के 1% से भी अधिक रहे। याचिकाकर्ता द्वारा अग्रिम लाइसेंस के

तहत किए गए आयातों संबंधी दूसरे कारण के संबंध में आयातकों का तर्क है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी की यह पद्धति है कि ऐसे उत्पादकों को पात्र घरेलू उद्योग से हटा दिया जाए। यह दलील दी गई है कि चीन से मेट्रोनिडाजोल के आयातों के मामले में तीन उत्पादकों को घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र से हटा दिया गया था जबकि इन कंपनियों ने ये आयात अग्रिम लाइसेंस के तहत किए थे। जहां तक याचिकाकर्ता के तीसरे इस कारण का संबंध कि अस्थायी रूप से बन्द रहने की स्थिति में आयात किए गए, आयातक ने यह दलील दी है कि उक्त कारण सभी तर्कों के विरुद्ध है क्योंकि एक स्थान पर घरेलू उद्योग का दावा है कि आयात करना उसकी अपनी निर्यात आवश्यकता के कारण जरूरी था और साथ ही यह कहा है कि आयात उक्त संयंत्र के अस्थाई रूप से बंद रहने के कारण किए गए। प्रकटन विवरण-पत्र के प्रत्युत्तर में आयातकों ने अपने उक्त रूख की पुनरावृत्ति की है।

घरेलू उद्योग ने नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग की परिभाषा के संबंध में कानूनी स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने तर्क दिया है कि उक्त रूल में आए शब्द 'सकेगा' को दिनांक 15.7.1999 के संशोधन संख्या 44/99 द्वारा 'सकें' के रूप में किया गया। इस प्रकार निर्दिष्ट प्राधिकारी में यह निर्णय करने के लिए निश्चित स्वविवेकी शक्तियां निहित थी कि क्या किसी मामले विशेष में आयातक घरेलू उद्योग को नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग का भाग माना जाए अथवा नहीं। मौजूदा मामले में प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट था कि याचिकाकर्ता को इस तथ्य के बावजूद पात्र घरेलू उद्योग माना जाएगा कि उन्होंने उक्त उत्पाद का आयात किया है। इस मामले में याचिकाकर्ता द्वारा आयात अग्रिम लाइसेंस पर किए गए जिन पर सीमा शुल्क तथा पाटनरोधी शुल्क से पूर्णतया छूट है। यह छूट इस तथ्य पर आधारित है कि ऐसे आयात देश के मुख्य व्यापार में शामिल नहीं होते हैं। विचाराधीन उत्पाद का आयात करने वाले उत्पादकों को हटाने का निर्णय प्राधिकारी द्वारा अलग अलग मामले के आधार पर, यथोचित तथा न्याय-संगत आधार पर और शामिल सभी कानूनी तथा आर्थिक पहलुओं पर विचार करने के बाद किया जाना चाहिए। कतिपय उत्पादकों को हटाए जाने संबंधी उपबंधों का प्रयोजन पाटित आयातों के प्रभाव का कोई प्रयोजन तथा अविकृत विचार होना चाहिए। यह नोट करना प्रासंगिक है कि मौजूदा याचिकाकर्ता ने पाटन पद्धति में किसी भी तरह से सहभागिता नहीं की है अथवा इसके प्रभाव से बचाव नहीं किया है अथवा उससे किसी भी तरह अवांछित लाभ नहीं उठाया है। आयातकों की यह धारणा कि घरेलू उद्योग को सामान्य रूप से हटा देना चाहिए, कानून के पाठन से अथवा इस विषय के क्षेत्राधिकार से साबित नहीं होता है। याचिकाकर्ता ने ईसी एंटी डंपिंग लॉ, ए

कमेंट्री ऑन रेग्यूलेशन 384/96 बाई निकोलस खान नामक पुस्तक से उद्धरणों का भी उल्लेख किया जिसमें इस संबंध में इसी द्वारा अपनाई गई पद्धतियों का उल्लेख है ।

याचिकाकर्ता द्वारा आगे यह भी दलील दी गई कि घरेलू उद्योग के मुद्दे पर प्रारंभिक निष्कर्षों की गलत व्याख्या की गई है और आयातकों द्वारा किए गए निवेदनों की तोड़-मरोड़कर व्याख्या की गई है । उपर्युक्त निष्कर्ष में यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयात की घरेलू उद्योग की स्थिति के निर्धारण में अनदेखी की गई है क्योंकि ये आयात निर्यात वचनबद्धता को पूरा करने के लिए जरूरी थे ने कि आयातकों/उपभोक्ताओं के निवेदनों में उल्लिखित कारणों की वजह से । निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्णय पर प्रश्न-चिन्ह लगाने के समर्थनकारी कारण प्रारंभिक निष्कर्षों की त्रुटिपूर्ण व्याख्या पर आधारित हैं और इसलिए इन्हें प्रारंभ से रद्द किए जाने की आवश्यकता है । आयातकों द्वारा उल्लिखित आयात मात्रा के 3% संबंधी मानदण्ड का कोई याचिका दायर करने हेतु घरेलू उद्योग की स्थिति से कोई संबंध नहीं है । फेनोल मामले में आयातकों द्वारा व्यक्त विश्वास भी पूर्णतया हानिकर तथा भ्रामक है ।

प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के मुद्दे पर प्रारंभिक निष्कर्षों के संबंध में आयातकों द्वारा दी गई दलील और याचिकाकर्ता द्वारा दी गई दलील की जांच की है। प्राधिकारी का विचार है कि नियम 2(ख) में प्राधिकारी को यह निर्णय का स्व:विवेक है कि क्या संबद्ध माल का आयात करने वाले घरेलू उत्पादक को घरेलू उद्योग का हिस्सा माना जाए अथवा उसे इससे हटा दिया जाए । मौजूदा मामले में भारत में संबद्ध माल के एकमात्र उत्पादक याचिकाकर्ता ने जांच अवधि के दौरान 32 मी.टन का आयात किया । ये आयात निर्यात उत्पादन के लिए किए गए थे और इनकी आवश्यकता उनके पैराक्रेसोल संसंत्र को सुनियोजित ढंग से बंद करने के कारण हुई थी । प्राधिकारी ने इन आयातों को पर्याप्त नहीं समझा, विशेष रूप से, जबकि ये निर्यात उत्पादन के लिए आशयित थे । घरेलू उद्योग की स्थिति के निर्धारण के संदर्भ में आयात मात्रा के 3% का मानदंड के संदर्भ का कोई मायने नहीं है क्योंकि ये उपबंध आयातों की डी-मिनिमस मात्रा के निर्धारण के संबंध में है । आयातकों द्वारा अपनी दलील के समर्थन में उल्लिखित अन्य मामलों के तथ्य तथा परिस्थितियां मौजूदा मामले से भिन्न हैं । अतः प्राधिकारी घरेलू मुद्दे के संबंध में अपने प्रारंभिक निष्कर्षों को दोहराता है और उनकी पुष्टि करता है ।

8. गौण स्रोतों पर आधारित सूचना की शुद्धता तथा पर्याप्तता

आयातकों की दलील है कि याचिका में डीजीसीआईएण्डएस के आंकड़ों पर विश्वास नहीं करने का कोई कारण नहीं दिया गया है। जांच आरंभ करते समय डीजीसीआईएण्डएस ने जांच अवधि के लिए अपने आंकड़ों का प्रकाशन किया था। दूसरे देशों से ऐसे भी आयात किए गए जो निर्धारित सीमा से अधिक हैं और जिनकी कीमतें काफी कम हैं।

याचिकाकर्ता द्वारा अपने पुनरुत्तर में यह दलील दी गई है कि जैसाकि याचिका में उल्लेख है, पैराक्रेसोल (कोड 2907 1201) से संबंधित डीजीसीआईएण्डएस के आंकड़ों पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वे सादेवार तथा मिश्रित विवरण के साथ उपलब्ध नहीं हैं। याचिका में आगे यह भी कहा गया है कि पैराक्रेसोल के संबंध में आईबीआईएस आयात आंकड़ों की बारीकी से जांच करते समय यह बात कई बार सामने आई थी कि क्रेसोल की अन्य किस्मों का वर्गीकरण पैराक्रेसोल के लिए आशयित कोड में किया गया जिससे आयात आंकड़ों में पूर्णतया विकार आ गया। चूंकि डीजीसीआईएण्डएस आंकड़ों में पर्याप्त विवरण के साथ आयातित क्रेसोल के सादेवार ब्यौरे शामिल नहीं थे इसलिए घरेलू उद्योग के लिए एक व्यावहारिक नहीं था कि डीजीसीआईएण्डएस आंकड़ों पर भरोसा कर पैराक्रेसोल के आयात के संबंध में आंकड़े तय किए जाएं। इसलिए उन्होंने आई बी आई एस आंकड़ों पर विश्वास किया जो कुछ प्रमुख पत्तनों की सीमाशुल्क दैनिक सूची पर आधारित हैं। आयातकों द्वारा प्रस्तुत डीजीसीआईएण्डएस के आंकड़ों से यह इंगित है कि आयात यूरोपीय यूनियन के अनेक देशों से हो रहे हैं। किन्तु तथ्य यह है कि संबद्ध माल का उत्पादक समूचे यूरोपीय यूनियन में केवल एक ही है जैसाकि चीन से होने वाले आयातों के विरुद्ध ईसी द्वारा जारी प्रारंभन नोटिस (2002/सी150/04) से जाहिर है। इस प्रकार डीजीसीआईएण्ड एस आंकड़ों पर इस आधार पर भी विश्वास नहीं किया जा सका।

आयातकों ने इस संबंध में प्रकटन विवरण के प्रत्युत्तर में दी गई अपनी दलीलों को दोहराया है।

प्राधिकारी ने डीजीसीआईएण्डएस के आंकड़ों की बजाय गौण स्रोत के आंकड़ों के आधार पर की जा रही याचिका के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा दी गई दलील की जांच की है। इस पक्ष की प्राधिकारी ने जांच आरम्भ के समय भी जांच

की थी । याचिकाकर्ता द्वारा यह भी स्पष्टीकरण दिया गया था कि शीर्ष 2907 1201 के तहत डीजीसीआईएण्डएस के आंकड़ों में क्रेसोल की अन्य किस्में भी शामिल थीं । याचिका में यह कहा गया है कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के तहत छह अंकों के स्तर (उप शीर्ष 2907.12) का एच एस कोड क्रेसोल की सभी किस्मों के संबंध में है और पैराक्रेसोल के लिए कोई अलग से विशिष्ट कोड नहीं दिया गया है । किंतु आई टी सी एच एस वर्गीकरण तथा डीजीसीआईएण्ड एस के पास आई अंकीय स्तर (2907 1201) शीर्ष का केवल एक अलग कोड है । इसलिए मेटाक्रेसोल, पैरामेटाक्रेसोल तथा मिश्रित क्रेसोल को आईटीसी एचएस 2907 1201 के तहत वर्गीकृत किया गया है । जानकारी का संकलन करते समय, ऐसे भी कई उदाहरण हैं जिनमें क्रेसोल की अन्य किस्मों को आईबीआईएस आंकड़ों के तहत भी कोड 2907 1201 के अंतर्गत पैराक्रेसोल के साथ वर्गीकृत किया जाता है । इसकी भी प्राधिकारी द्वारा पड़ताल की गई है । याचिका में यह भी कहा गया है कि चूंकि डीजीसीआईएण्डएस के आंकड़ों में आयातित क्रेसोल का विस्तृत सौदेवार विवरण नहीं दिया गया है । इसलिए घरेलू उद्योग के लिए यह व्यावहारिक नहीं है कि डीजीसीआईएण्डएस के आंकड़ों से क्रेसोल की विभिन्न किस्मों को पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ अलग कर दिया जाए । याचिका में यह भी कहा गया है कि भारत मेटाक्रेसोल तथा मेटापैराक्रेसोल का आयात चीन से इतर अन्य देशों से करता है । भारत को इन क्रेसोलों के प्रमुख निर्यातक दक्षिण अफ्रीका, जापान, जर्मनी तथा संयुक्त राज्य अमरीका हैं । मेटाक्रेसोल तथा मेटापैराक्रेसोल के ये आयात अन्य अंतिम प्रयोगों/उपयोगों के प्रयोजनार्थ हैं और इसलिए वे घरेलू उद्योग के हित से विरुद्ध नहीं हैं । आयातकों ने भी कोई ऐसे निश्चायक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं जिनमें आयात उत्पादों के विवरण-युक्त सौदेवार आयातों के रूप में अन्य देशों से पैराक्रेसोल के आयात दर्शाए गए हों । ऐसी परिस्थितियों में प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत गौण स्रोतों पर आधारित आयात साक्ष्य पर भरोसा किया है।

9. पूर्णतया त्रुटियुक्त अगोपनीय याचिका

आयातक द्वारा दलील दी गई है कि अगोपनीय याचिका में गोपनीय याचिका में विहित जानकारी के सार की यथोचित समझ की अनुमति नहीं है । लगभग सभी आंकड़ों को गोपनीय माना गया है जोकि नियमावली के अनुसार अनुचित तथा असमर्थित है । आयातक ने संपूर्ण जानकारी को संकेत मात्र समझा है ।

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि आयातक द्वारा दायर प्रश्नावली प्रत्युत्तर बहुत ही अपर्याप्त, चुनिंदा तथा सारहीन है। विशेष रूप से, मैसर्स नन्दोलिया तथा मैसर्स यूनिवर्सल केमिकल एण्ड इंडस्ट्रीज लि० ने कोई अगोपनीय हिस्सा इस बहाने पर प्रस्तुत नहीं किया है कि संगत जानकारी संवेदनशील है। इन पक्षकारों को इस बात के लिए बाध्य किया जाए कि वे सही उत्तर को संज्ञान में लिए जाने से पहले प्रस्तुत कर दें। जहां तक याचिकाकर्ता की अगोपनीय जानकारी का संबंध है उन्होंने कहा है कि उन्होंने अगोपनीय जानकारी दे दी है जिसमें सारांशीकरण/सूचीकरण हेतु परीक्षणीय गोपनीय जानकारी की सीमा तक सूचीबद्ध जानकारी शामिल है।

प्राधिकारी ने इन दलीलों की जांच की है। याचिकाकर्ता ने ऐसी अगोपनीय जानकारी दी थी जिसमें आयातों से संबंधित जानकारी शामिल थी। कुल मांग, याचिकाकर्ता का बाजार हिस्सा, उत्पादन तथा क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, बिक्री मूल्य तथा इकाई कीमत के संबंध में सूचीबद्ध जानकारी भी प्रदान की गई है। याचिकाकर्ता ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट भी दर्शाई जिसे सार्वजनिक फाइल में प्रस्तुत किया गया। प्राधिकारी का विचार है कि नियम 7(1) के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा गोपनीय मानी गई जानकारी को गोपनीय समझा जाए और जहां तक संभव हो सके, याचिकाकर्ता ने अगोपनीय सारांश नियम 7(2) के अनुसार उपलब्ध करा दिया है।

ग. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन संबंधी दावों की जांच

10.. प्राधिकारी सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में प्रारंभिक निष्कर्षों का स्मरण करता है। प्रारंभिक निष्कर्षों के स्तर पर निम्नलिखित दो निर्यातकों से प्रत्युत्तर प्राप्त हुए थे :-

- (i) मैसर्स नेनजिंग लॉंग्यान केमिकल कंपनी लि० चीन
- (ii) मै० नेनजिंग जिंगमेई केमिकल कंपनी लि० चीन

प्राधिकारी ने नोट किया था कि इन दो निर्यातकों ने इस आधार पर बाजार अर्थव्यवस्था/व्यक्तिगत व्यवहार दिए जाने का दावा किया था कि वे स्वतंत्र रूप से उत्पादन तथा व्यापार क्रियाकलापों का प्रचालन करते हैं, सप्लायरों तथा ग्राहकों को मुक्त रूप से चुनते हैं और बाजार के संकेत के प्रत्युत्तर में बिक्री बाजार विकसित करते हैं। किन्तु प्राधिकारी ने यह पाया था कि पैराग्राफ 8 में उप पैरा (3) में उल्लिखित मानदंडों के आधार पर पर्याप्त साक्ष्य तथा जानकारी प्रस्तुत नहीं की थी

जिससे इस कल्पना का खंडन हो सके कि निर्यातक गैर बाजार अर्थव्यवस्था के हैं । इसलिए प्राधिकारी उपर्युक्त नियमावली के अनुबंध 1 के पैराग्राफ 1 से 6 में निर्धारित सिद्धांतों को लागू नहीं कर सका है और 'उपलब्ध तथ्यों' के अनुसार कार्रवाई करने पर बाध्य रह गया । इसके अलावा, प्राधिकारी ने पाया है कि प्रश्नावली के परिशिष्ट 8 तथा 9 में वांछित उत्पादन लागत संबंधी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत जानकारी अपूर्ण तथा गलत थी । कच्चे माल के संबंध में अंतिम उत्पाद में लगाए गए प्रत्येक कच्चे माल का अनुपात नहीं दर्शाया गया : पैराक्रेसोल की लागत निर्धारण का आधार भी नहीं बताया गया । जांच अवधि के लिए उपलब्ध वित्तीय विवरण अर्थात् लाभ तथा हानि लेखा, तुलन-पत्र तथा उत्पादन लागत पड़ताल योग्य नहीं पाई गई । चूंकि प्रस्तुत जानकारी के आधार पर प्राधिकारी उत्पादन लागत की पड़ताल नहीं कर सका इसलिए घरेलू बिक्री सौदे सामान्य व्यापार क्रियाकलाप के लिए नहीं पाए गए । प्राधिकारी ने अपने दिनांक 17 जनवरी, 2003 के पत्र द्वारा संबंधित निर्यातकों को प्रस्तुत जानकारी में पाई गई कमियों की विस्तृत जानकारी अलग से दे दी थी ।

अतः इन परिस्थितियों में नियमानुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण नियम 6(8) के अनुसार 'उपलब्ध तथ्यों' के आधार पर अनंतिम तौर पर कर दिया गया । इस प्रकार याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार अनुमानित उत्पादन लागत जमा बिक्री, प्रशासनिक तथा सामान्य प्रभारों और यथोचित लाभ-शशि के संबंध में उपलब्ध जानकारी को चीन जनवादी गणराज्य में संबद्ध माल के सामान्य मूल्य का हिसाब लगाने हेतु आधार मान लिया गया है । घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत उत्पादन लागत संबंधी साक्ष्य पर विचार करते समय प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की वास्तविक उत्पादन लागत को अनुकूल दक्षता-स्तर पर मानकीकृत करके उल्लेख किया था ।

प्रारंभिक निष्कर्षों के बाद किसी भी निर्यातक से प्रारंभिक निष्कर्षों के संबंध में अथवा सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात् अथवा प्रकटन विवरण-पत्र पर कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । अतः प्राधिकारी सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन के संबंध में अपने प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि करता है ।

पाटन मार्जिन

11. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 में निर्धारित सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन के निर्धारण के संचालन संबंधी सिद्धांतों की सतत पद्धति का अनुसरण किया है । पाटन मार्जिन का निर्धारण उक्त नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 6 में निर्धारित सिद्धांत के अनुसरण में निर्यात कीमत की उचित

तुलना सामान्य मूल्य से करने के आधार पर किया गया है। यह तुलना व्यापार के उसी स्तर अर्थात् कारखानागत स्तर पर की गई है। यथाउपर्युक्त निर्धारण अनुसार सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत के आधार पर प्राधिकारी निम्नलिखित पाटन मार्जिन(%) को अंगीकार करने की पुष्टि करता है :

| क्र.स. | निर्यातक का नाम | पाटन मार्जिन % |
|--------|---|----------------|
| 1. | मै. नेनजिंग जिगमेई केमिकल कं० लि० चीन | 40.74% |
| 2. | मैसर्स नेनजिंग लोंग्यान केमिकल कं० लि०, चीन | 31.94% |
| 3. | चीन जनवादी गणराज्य के अन्य निर्यातक | 45.04% |

घ. क्षति तथा क्षति की आशंका

12. पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में निम्नलिखित व्यवस्था है:-

'क्षति का निर्धारण'

- (1) विनिर्दिष्ट देशों से हुए आयातों के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी आगे अपने निष्कर्ष दर्ज करेंगे कि भारत में होने वाले ऐसे आयातों से भारत में स्थापित किसी उद्योग को वास्तविक क्षति होती है अथवा क्षति का खतरा उत्पन्न होता है अथवा किसी उद्योग को स्थापित करने में बाधा आती है :
- (2) निर्दिष्ट प्राधिकारी घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति, घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के खतरे और घरेलू उद्योग की स्थापना में आने वाली वास्तविक बाधा और पाटित आयातों की मात्रा और समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर इसके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव समेत सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इन नियमों के अनुबंध II में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार पाटित आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का निर्धारण करेंगे ।

13. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में उल्लिखित/क्षति निर्धारण संबंधी सिद्धांतों में यह निर्धारित है कि:

(क) क्षति के निर्धारण में (क) पाटित आयातों की मात्रा तथा समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव तथा (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव दोनों की वस्तुपरक जांच शामिल होगी।

(ख) पाटित आयातों के मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत की तुलना में काफी वृद्धि हुई है। नियम 18 के उप नियम (2) में यथा उल्लिखित कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा काफी हद तक कीमतों में कमी लाना अथवा कीमत की उस वृद्धि को रोकना है जोकि अन्यथा काफी हद तक बढ़ गई होती।

14. आयातक के विचार

- (i) जहां तक आयातों का संबंध है इस उत्पाद को समर्पित सीमा शुल्क उप शीर्ष में वर्गीकृत किया गया है, फिर भी डीजीसीआईएण्डएस के आंकड़ों की अनदेखी की गई है। आयातों में वृद्धि हुई है। किन्तु यह वृद्धि मुख्य रूप से तीन कंपनियों द्वारा पीएए के उत्पादन के आरंभ होने के कारण हुई है। चूंकि याचिकाकर्ता इस जरूरत को पूरा नहीं करता है इसलिए इन आयातों के कारण क्षति नहीं हो सकती है।
- (ii) याचिका में उत्पादन के सूचीबद्ध आंकड़ों के अनुसार वृद्धि हुई है जबकि याचिका में कहीं और यह कहा गया कि घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट आई है।
- (iii) अनुप्रवाह उत्पादों के उत्पादक पैराक्रेसोल के उपभोक्ता हैं। उन्हें व्यापार से बाहर करने के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग ने याचिका दायर की है।
- (iv) बिक्री मात्रा में काफी वृद्धि हुई है। बाजार हिस्से अथवा क्षमता उपयोग में गिरावट का संबंध आयातों के साथ नहीं मिलाया जा सकता। घरेलू उद्योग की कैप्टिव खपत में गिरावट आई है और इसे आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का एक आधार नहीं माना जा सकता है। याचिकाकर्ता की

वार्षिक रिपोर्ट में यह बात स्वीकार की गई है कि प्रयोक्ता उद्योग के साथ प्रतिस्पर्धा का कारण कीमतों में गिरावट का होना है ।

- (v) यदि बिक्री कीमत में व्यापार कीमत तथा पहुंच मूल्य में वृद्धि होने की स्थिति में गिरावट आई भी हो तब भी इसका कारण तथाकथित पाटित आयात नहीं हो सकता है ।
- (vi) घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत (उत्पाद शुल्क सहित) में वृद्धि हुई है, जैसाकि उक्त कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट से स्पष्ट है । जांच की अवधि में उत्पादन लागत में गिरावट आई है । बिक्री कीमत में वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में वृद्धि हुई है ।
- (vii) आंकड़ों में परस्पर विरोध रहा है क्योंकि उत्पादन में वृद्धि, बिक्री में वृद्धि और स्टॉक में वृद्धि से भी वृद्धि दर्शाई गई है ।
- (viii) इस माल की मांग तथा सप्लाई के बीच काफी अंतर है । अतः पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी उपभोक्ताओं के पास इस माल को आयात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा ।
- (ix) चूंकि चीन से किए गए आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना में अधिक है, इसलिए ऐसे आयातों को क्षति का अथवा घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति की आशंका का कारण नहीं माना जा सकता है । इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा एन टी सी एफ के मामले में हाल ही में अधिसूचित अंतिम निष्कर्षों को देखा जा सकता है जिसमें प्राधिकारी ने निर्णय यह दिया कि पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच ऋणात्मक कटौतीगत कीमत विद्यमान रहने के कारण कोई कारणात्मक संबंध नहीं है ।
- (x) बिक्रीगत कीमत पाटन के कारण तथाकथित क्षति का कारण नहीं हो सकती है । यह समझ में नहीं आता है कि आयातों के परिणामस्वरूप बाजार में बिक्रीगत कीमत किस प्रकार मानी गई है ।
- (xi) दूसरे देशों से तुलनीय अथवा अपेक्षतया कम कीमतों पर आयात किए गए, अतः कारणात्मक संबंध साबित नहीं होता है ।
- (xii) आयातों में वृद्धि पीएए के उत्पादकों द्वारा किए गए आयातों के कारण हुई है जो हाल ही में अस्तित्व में आए हैं और जिन्हें घरेलू उद्योग अपना माल बिल्कुल भी बेच नहीं रहा है । अतः इन उपभोक्ताओं द्वारा किए गए उत्पाद को घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का कारण नहीं माना जा सकता है ।

पैराक्रेसोल कंज्यूमर्स एसोसिएशन ने प्रकटन विवरण पत्र के प्रत्युत्तर में निम्नलिखित दलीलें व्यक्त की हैं :

- (i) याचिकाकर्ता पीएए के उत्पादकों को माल की सप्लाई नहीं करता है । याचिकाकर्ता ने प्रयास किया कि अन्य उत्पादकों को हटाने के उद्देश्य से पीएए के सुचारु वाणिज्यिक उत्पादन में सभी बाधाएं तैयार की जाएं ।
- (ii) याचिकाकर्ता की अपनी स्वीकृति के अनुसार हुए 99% शुद्धता वाले पैराक्रेसोल की सप्लाई का उल्लेख नहीं करते ।
- (iii) आयातों में 99% का पैराक्रेसोल शामिल है । आयातों में होने वाली वृद्धि की जांच करते समय यह अपेक्षित होगा कि इन्हें हटा दिया जाए क्योंकि याचिकाकर्ता न तो इस माल की सप्लाई करता है और न ही वे इसकी सप्लाई करने के इच्छुक हैं ।
- (iv) याचिकाकर्ता का इरादा है कि मांग को पूरा करने के प्रयोजनार्थ क्षमता का विस्तार किया जाए । इस दलील में भ्रांति है क्योंकि याचिकाकर्ता (क) अप्रयुक्त क्षमता का दावा कर रहा है, (ख) 99% शुद्धता वाले पैराक्रेसोल की सप्लाई के लिए खेद प्रकट कर रहा है और (ग) उसकी बिक्री मात्रा में वृद्धि हो रही है फिर भी क्षमता विस्तार का दावा कर रहा है ।

15. घरेलू उद्योग के विचार

आयातकों की टिप्पणियों के प्रत्युत्तर में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित दलीले दी हैं:-

(क) मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता

इस बात का पहले ही स्पष्टीकरण कर दिया गया है कि याचिकाकर्ता की पैराक्रेसोल विनिर्माण करने की क्षमता 5500 मी.टन है जोकि पैराक्रेसोल की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त है । घरेलू उद्योग की यह भी योजना है कि वह अपनी क्षमता बढ़ाकर 10,000 मी.टन कर दे ताकि बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके।

(ख) आयातक द्वारा भ्रामक तथा गलत वक्तव्य

आयातकों ने आवेदन-पत्र के अगोपनीय हिस्से और प्रारंभिक निष्कर्षों के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से गलत वक्तव्य दिया है । आयातकों द्वारा इस बात का उल्लेख किया

गया है कि प्रारंभिक निष्कर्ष क्षमता उपयोग में वृद्धि को इंगित करते हैं जबकि तथ्य यह है कि प्रारंभिक निष्कर्षों के पैरा 29 में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने निष्कर्षों में यह लिखा है कि क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। जाहिर है कि जांच अवधि के दौरान क्षमता उपयोग में वृद्धि की इस झूठी भूमिका पर आधारित सभी दलीलों को कायम नहीं रखा जा सकता है। याचिका के पृष्ठ 9 तथा 14 में दिए गए उत्पादन आंकड़ों में विरोधाभास के संबंध में आयातक का वक्तव्य गलत तथा भ्रामक है। घरेलू उद्योग ने पृष्ठ 14 पर स्पष्ट रूप से यह इंगित किया है कि जांच-अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में गिरावट आई है जोकि पृष्ठ 9 में दिए गए वक्तव्य के अनुरूप है।

(ग) बिक्री कीमत

आयातकों ने दलील दी थी कि जांच अवधि के दौरान बिक्री कीमत में वृद्धि हुई है। यह दावा घरेलू उद्योग के तुलन-पत्र पर आधारित बताया जाता है। आवेदन-पत्र के अगोपनीय हिस्से में स्पष्ट रूप से यह दर्शाया गया है कि बिक्री कीमतों में जांच-अवधि के दौरान पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में तीव्र गिरावट आई है।

(घ) बिक्रीगत कीमत/कटौतीगत कीमत और घरेलू उद्योग को क्षति

आयातकों ने निवेदन किया है कि चूंकि आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना में अधिक है। अतः इन आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति अथवा वास्तविक क्षति की आशंका नहीं हो सकती है। इस संबंध में आयातकों ने निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा एनटीसीएफ के मामले में लिए गए निर्णय का उल्लेख किया है जिसमें यह निर्णय लिया गया कि ऋणात्मक कटौतीगत कीमत के विद्यमान रहने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को पाटित आयातों और वास्तविक क्षति में कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। एनटीसीएफ का मामला पुनरीक्षा के लिए है न कि नई जांच करने के लिए। प्रतिवादी द्वारा व्यक्त विश्वास पूर्णतया पथभ्रमित है क्योंकि नियम 23 के तहत पुनरीक्षा के लिए अपनाए गए मानदंड पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में निर्धारित मानदंडों से बिल्कुल ही भिन्न हैं। इस नियमावली में यह

अपेक्षा है कि आयात मात्रा के प्रभाव का मूल्यांकन कटौतीगत कीमत अथवा कीमत दबाव अथवा कीमत मंदी के अनुसार किया जाए। अतः यह दावा कि कटौतीगत कीमत के अभाव में आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति अथवा वास्तविक क्षति की आशंका नहीं हो सकती है, कानून के उपबंधों से साबित नहीं होती है।

जैसाकि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षों में निर्णय लिया, हमारा यह निर्णय है कि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का सर्वाधिक पर्याप्त कारण बिक्रीगत कीमत का होना है। संबद्ध देश से संबद्ध माल के अपेक्षतया कम पहुंच मूल्य के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग अपने उत्पादों के लिए उचित एवं यथोचित कीमत प्राप्त नहीं कर सका है जिसके कारण कीमत में जबरदस्त मंदी आई है। इसके फलस्वरूप पूंजी-निवेश पर ऋणात्मक आय प्राप्त हुई है। पैराक्रेसोल विनिर्माण उद्योग में भारी पूंजी निवेश किया गया है और बिक्री आय के फलस्वरूप उद्योग द्वारा किए गए पूंजी निवेश पर हानि तथा ऋणात्मक आय प्राप्त हुई है जो हुई क्षति से परिलक्षित होता है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने कई मामलों में कीमत दबाव के आधार पर क्षति के संबंध में सकारात्मक निष्कर्ष दिए हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

16. प्राधिकारी ने अन्तिम निर्णयन के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित क्षति मानदंडों की जांच की है :

आयात, घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा, संबद्ध देश से आयात, बाजार हिस्से में परिवर्तन, उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा तथा मूल्य, निवल बिक्री आय, माल सूची, रोजगार, मजदूरियां, लाभप्रदता, पूंजी निवेश पर आय, पाटन पर मार्जिन की मात्रा, आदि।

17. प्राधिकारी ने क्षति के संबंध में याचिकाकर्ता तथा आयातकों/निर्यातकों द्वारा दी गई विभिन्न दलीलों की भी जांच की है। प्राधिकारी को आयातक का यह दावा सही नहीं लगता है कि याचिका के पृष्ठ 9 तथा 14 में उल्लिखित उत्पादन आंकड़ों में कोई विरोधाभास सही है। इसी प्रकार, प्राधिकारी को क्षमता उपयोग में वृद्धि के संबंध में आयातक का दावा गलत लगता है। प्राधिकारी ने पैरा 29 के तहत प्रारंभिक निष्कर्षों में क्षमता उपयोग का निम्नलिखित स्तर पाया :-

! प्राधिकारी पाता है कि घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग में जांच अवधि के दौरान गिरावट आई है जैसा कि नीचे दी गई सारणी में परिलक्षित होता है

| वर्ष | क्षमता उपयोग % |
|----------------------|----------------|
| 1999-2000 | 61.78% |
| 2000-2001 | 67.71% |
| 2001-2002(जांच अवधि) | 62.80% |

(सूचीबद्ध)

18. जहां तक बिक्री कीमत का संबंध है प्राधिकारी वर्ष 2001-2002 के लिए उक्त कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को नोट करता है। ऐरोमेटिक डिवीजन के निष्पादन से यह प्रदर्शित होता है कि ' मांग की तुलना में सप्लाई काफी अधिक है और प्रतिस्पर्द्धियों के आक्रामक विपणन से कीमत ढांचे पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस डिवीजन को कीमतों में काफी गिरावट करनी होगी जिससे कि बाजार हिस्सा बना रहें प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की निवल बिक्री आय की भी जांच की है और पाया कि उसमें जांच अवधि के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में काफी गिरावट आई है।

संबद्ध देश से आयात

19. याचिका के अनुसार संबद्ध देश से आयात 1999-2000 में 264.4 मी० टन, 2000-2001 में 724 मी० टन और जांच अवधि 2001-2002 के दौरान 586 मी० टन के हुए थे। तथापि निर्यातकों/आयातकों से प्राप्त सूचना के अनुसार प्राधिकारी यह पाते हैं कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से पैराक्रैसोल के 1217.87 मी० टन के आयात हुए थे। प्राधिकारी यह पाते हैं कि संबद्ध देश से हुए आयातों में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान 68% तक की वृद्धि हुई है। तथापि कुल आयातों में संबद्ध देश से हुए आयातों का हिस्सा पूर्ववर्ती वर्ष के 99.72% और 1999-2000 के 68.82% के हिस्से की तुलना में जांच अवधि के दौरान बढ़कर 100% हो गया है। प्राधिकारी यह पाते हैं कि संबद्ध देश से पाटित आयातों में समग्र रूप से अत्यधिक वृद्धि हुई है।

बाजार हिस्सा:

20. प्राधिकारी यह पाते हैं कि संबद्ध वस्तु की मांग में घरेलू उद्योग और संबद्ध देश से हुए आयात का बाजार हिस्सा निम्नानुसार रहा है:-

| | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002(जांच अवधि) |
|--------------------------------|-----------|-----------|----------------------|
| घरेलू उद्योग का हिस्सा (%) | 49.67% | 27.68% | 30% |
| संबद्ध देश से आयातों का हिस्सा | 34.54% | 72% | 70% |

संबद्ध वस्तु की कुल मांग में संबद्ध देश से हुए आयातों का बाजार हिस्सा 1999-2000 में 34.54% से बढ़कर जांच अवधि के दौरान 70% हो गया है। तथापि पूर्ववर्ती वर्ष में बाजार हिस्सा 72% से कम हुआ है। जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की कुल मांग में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट नहीं आई है। यह 2000-2001 के दौरान 27.68% से बढ़कर जांच अवधि के दौरान 30% हो गया है।

क्षमता उपयोग

21. प्राधिकारी यह पाते हैं कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट आई है जैसाकि निम्नलिखित तालिका से प्रदर्शित होता है:-

| वर्ष | क्षमता उपयोग (%) |
|----------------------|------------------|
| 1999-2000 | 61.78% |
| 2000-2001 | 67.71% |
| 2001-2002(जांच अवधि) | 62.80% |

(सूचीकृत)

बिक्री मात्रा:

22. घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा 2000-2001 में *** से बढ़कर जांच अवधि में *** हो गई है तथा सूचीकृत आंकड़े निम्नानुसार हैं :-

| वर्ष | बिक्री मात्रा(मी.टन) |
|----------------------|----------------------|
| 1999-2000 | 100 |
| 2000-2001 | 69 |
| 2001-2002(जांच अवधि) | 130 |

माल सूची:

23. प्राधिकारी यह पाते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा भारत तैयार माल की भंडार सूची में मार्च, 2001 को समाप्त पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में मार्च, 2002 में वित्त वर्ष की समाप्ति पर पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसमें *** % की वृद्धि प्रदर्शित हुई है।

रोजगार:

24. जांच अवधि में रोजगार में मामूली गिरावट आई है।

मजदूरी:

25. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मजदूरी लागत में वृद्धि हुई है।

लाभप्रदत्ता

26. प्राधिकारी ने कुछ आयातों को उपयोक्ताओं के इन तर्कों पर ध्यान दिया है कि मै0 अतुल लि0 की एरोमैटिक डिबीजन भारी मुनाफा कमाती हैं और इसलिए घरेलू उद्योग-क्षति का दावा नहीं कर सकता। मै0 अतुल लि एरोमैटिक डिबीजन में अनेक उत्पादों का निर्माण करती है और पैराक्रैसोल उनमें से एक उत्पाद है।

प्राधिकारी यह पाते हैं कि संबद्ध वस्तु के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति पर संबद्ध वस्तु के पाटन का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। याचिकाकर्ता को संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के कम कीमत के प्रस्तावों/आयातों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी थी। बिक्री लागत, बिक्री प्राप्ति से अधिक रही है इसके परिणामस्वरूप जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के विनिर्माण और बिक्री में घरेलू उद्योग को घाटा हुआ है। अतः प्राधिकारी यह पाते हैं कि घरेलू उद्योग को पैराक्रैसोल से संबंधित विनिर्माण में घाटा हुआ।

लगाई गई पूंजी पर आय

27. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पैराक्रैसोल का विनिर्माण अत्यधिक पूंजी गहन होता है। उचित लाभ कमाने की बजाए घरेलू उद्योग को पैराक्रैसोल की बिक्री पर वस्तुतः *** रूप प्रति मी० टन का घाटा हो रहा है। अतः घरेलू उद्योग को पैराक्रैसोल के प्रति मी० टन उत्पादन पर लगाई गई प्रभावी पूंजी पर *** % का घाटा हो रहा है।

कम कीमत पर बिक्री

28. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की अहानिकर कीमत की तुलना संबद्ध माल के आयातों के पहुंच मूल्य के साथ की है और यह पाया है कि पाटित आयातों के परिणामस्वरूप काफी कम कीमत पर बिक्री की गई है :

| | |
|-------------|------------|
| एनआईपी | *** |
| पहुंच मूल्य | *** |
| बिक्रीगत % | *** (सका.) |

नकदी प्रवाह पर वास्तविक एवं संभावित ऋणात्मक प्रभाव

29. प्राधिकारी यह पाता है कि घरेलू उद्योग पैराक्रैसोल के विनिर्माण हेतु लगाई गई पूंजी पर मामूली आय भी प्राप्त नहीं कर सका है। माल सूची स्तर भी ऊंचा रहा है। अतः घरेलू उद्योग के नकदी प्रवाह पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है।

वृद्धि

30. प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के उद्देश्य से विस्तार करने की योजना बना रहा है।

31. क्षति के संबंध में निष्कर्ष:

- संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों में समग्र रूप में वृद्धि हुई है।
- वर्ष 1999-2000 की तुलना में जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से पाटित आयातों के बाजार हिस्से में पर्याप्त वृद्धि हुई है। तथापि, पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान इसमें मामूली गिरावट आई है।

- iii) घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वर्ष 2000-01 की तुलना में जांच अवधि के दौरान गिरावट आई है और यह पाटित आयातों के कारण अक्षतिकर कीमत से कम रही है ।
- iv) घरेलू उद्योग को कीमत ह्रास के कारण क्षति हुई है । वे अपनी बिक्री कीमत को नहीं बढ़ा सके जिससे कि वे निवेशों पर उचित आय प्राप्त कर सकें क्योंकि पाटित आयातों के पहुंच मूल्य से घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में पर्याप्त रूप से कमी हुई मे ।
- v) प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालता है कि घरेलू उद्योग की क्षति का सबसे महत्वपूर्ण कारण कम कीमत पर बिक्री का होना है । संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के अपेक्षतया कम पहुंच मूल्य के परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग अपने उत्पादों की उचित कीमत प्राप्त नहीं कर सका है । इससे निवेश पर ऋणात्मक आय प्राप्त हुई है । पैराक्रैसोल विनिर्माण उद्योग में निवेश काफी अधिक है और बिक्री आय में हुई हानि के परिणामस्वरूप उद्योग द्वारा किए गए पूंजी निवेश पर हानि तथा ऋणात्मक आय प्राप्त हुई जिससे उद्योग को हुई क्षति परिलक्षित होती है ।
- vi) उपर्युक्त आर्थिक मापदंड संची और सामूहिक रूप से यह साबित करते हैं कि घरेलू उद्योग को पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है ।

ड. कारणात्मक संबंध

32. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के सिद्धांत (v) के अनुसार घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच की है । इस नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iv) में यथा निर्धारित संगत संकेतकों की प्राधिकारी द्वारा जांच की गई है ।
33. प्राधिकारी ने कारणात्मक संबंध के बारे में याचिकाकर्ता और अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर विचार किया जिनका उल्लेख पूर्वोक्त पैराग्राफों में किया गया है । ऊपर दिए गए विभिन्न आर्थिक मापदंडों की जांचकरन के पश्चात प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचे हैं:-
34. प्राधिकारी पाता है कि संबद्ध देश से पाटित आयातों के परिणामस्वरूप बिक्रीगत कीमत काफी रही है । संबद्ध देश से संबद्ध माल के आयात के अपेक्षतया कम पहुंच मूल्य के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग अपने उत्पादों के लिए उचित एवं यथोचित कीमत प्राप्त नहीं कर सका है । पैराक्रैसोल के उत्पादन में भारी पूंजी निवेश

लगा हुआ है और उद्योग द्वारा पूंजी निवेश पर प्राप्त कम आय से उद्योग को हुई क्षति परिलक्षित होती है संबद्ध माल की मांग में गिरावट नहीं आई है बल्कि उसमें वृद्धि हुई है और इसलिए मांग में कमी होना क्षति का कारण नहीं माना जा सकता है। प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि घरेलू उद्योग विश्व-व्यापी स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी है और घरेलू उत्पादकों में प्रौद्योगिकीय अथवा प्रतिस्पर्द्धी में परिवर्तन क्षति का कारण प्रतीत नहीं होता है। उद्योग में प्रौद्योगिकीय विकास अथवा कोई अन्य कारण जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो, दिखाई नहीं दिया है।

घरेलू उद्योग के लिए समान उत्पादों के संबंध में अक्षतिकर कीमत का निर्धारण करते समय प्राधिकारी ने संबद्ध माल की वास्तविक उत्पादन लागत का प्रयोग घरेलू उद्योग की अनुकूल उत्पादन लागत के निर्धारण में किया है जिसे मानकीकृत सर्वोत्तम खपत मानदंडों और कच्चे माल की वास्तविक कीमत को ध्यान में लिया गया और जिस कच्चे माल की खपत जांच अवधि के दौरान संबद्ध माल के उत्पादन में किया गया हो।

च. भारतीय उद्योग के हित

35. पाटनरोधी शुल्क लगाने का सामान्य तौर पर उद्देश्य ऐसे पाटन को समाप्त करना है जिससे भारतीय उद्योग को नुकसान हो रहा है तथा भारतीय बाजार में ऐसी खुली एवं उचित प्रतिस्पर्द्धा की पुनः स्थिति लाना है जो कि देश के सामान्य हित में है।

36. प्राधिकारी यह मानता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध माल का प्रयोग करते हुए विनिर्मित उत्पाद का कीमत स्तर प्रभावित होगा और परिणामस्वरूप, इन उत्पादों की तुलनात्मक प्रतिस्पर्द्धा पर उसका प्रभाव पड़ेगा। किन्तु, पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्द्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्क लगाने से पाटित पद्धतियों द्वारा प्राप्त अनुचित लाभों को समाप्त किया जा सकेगा, घरेलू उद्योग की मन्दी को रोका जा सकेगा और संबद्ध माल के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध होने में सहायता मिलेगी। प्राधिकारी नोट करता है कि पाटनरोधी उपायों से संबद्ध देशों से आयात किसी भी प्रकार रोका जा सकेगा, इसलिए, उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।

छ. निष्कर्ष

37. पूर्वोक्त पर विचार करने के पश्चात् प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि

उत्पादों की कीमतें भारत के विनिर्मित सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर

- (ii) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है : तथा
 (iii) यह वास्तविक क्षति संबद्ध देश से संबद्ध माल के पाटित आयातों द्वारा संचयी कारणों से हुई है ।

38. यह आवश्यक समझा जाता है कि संबद्ध माल के आयातों पर निश्चित पाटनरोधी लगाया जाए । तदनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देश से पैराक्रैसोल के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करता है ।

39. यह निर्णय लिया जाता है कि पाटन मार्जिन के बराबर अथवा उससे कम राशि का पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाए, जिसके लगाए जाने की फलस्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति समाप्त होगी । आयातों की पहुंच कीमत की तुलना घरेलू उद्योग की अक्षितिकर कीमत से की गई जिसका निर्धारण जांच अवधि के लिए किया गया । तदनुसार ऐसा प्रस्ताव है कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पैराक्रैसोल पर निश्चित पाटनरोधी शुल्क लगा दिया जाए जिसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची-I के शीर्ष 2907.12 के तहत क्लीयर किया जा रहा है । पाटनरोधी शुल्क नीचे दी गई सारणी के कालम 9 में उल्लिखित राशि तथा संबद्ध माल के आयात के अमरीकी डालर प्रति मी.टन के पहुंच मूल्य के बीच का अंतर होगा ।

| क्र.सं | उप शीर्ष | माल का विवरण | निर्देशन | उद्भव का देश | निर्यात का देश | उत्पादक | निर्यातक | राशि | माप की इकाई | मुद्रा |
|--------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|----------------|-----------------|---------|-------------|--------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | 2907.12 | पैराक्रैसोल | - | कोई भी देश | चीन | कोई भी उत्पादक | कोई भी निर्यातक | 2220.95 | एम.टा | अम.डा. |
| 2 | 2907.12 | पैराक्रैसोल | - | चीन | कोई भी देश | कोई भी उत्पादक | कोई भी निर्यातक | 2220.95 | एम.टा | अम.डा. |

40. इस प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम 1962 और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 तथा 9क के तहत वसूले जाने वाले शुल्कों को छोड़कर सभी सीमा शुल्कों के तहत निर्धारित मूल्यांकन योग्य मूल्य होगा ।

41. उपरोक्त के अध्यक्षीन प्राधिकारी दिनांक 17 जनवरी, 2003 के प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि करता है ।

42. इस आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण में उपर्युक्त अधिनियम के अनुसार दायर की जा जा सकेगी।

एल. वी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2003

Final Findings

Subject : Anti-dumping investigation concerning import of Para Cresol originating in or exported from People's Republic of China.

No. 14/29/2002-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof.

A. PROCEDURE:

2. The procedure described below has been followed with regard to the investigations:-

i) The Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), under the above Rules, received a written petition from M/s. Atul Ltd., Gujarat, representing the domestic industry, alleging dumping of Para Cresol (hereinafter referred to as subject goods) originating in and exported from Peoples' Republic of China (hereinafter referred to as subject country);

ii) The preliminary scrutiny of the application revealed certain deficiencies, which were subsequently rectified by the petitioner. The petition was thereafter, considered as properly documented;

(iii) The Authority notified the Embassy of People's Republic of China in India about the receipt of dumping application made by the petitioner before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra;

(iv) The Authority issued a Public Notice dated 27th August 2002 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti dumping proceedings concerning imports of Para Cresol covered under Chapter heading/subheading 2907.12 of Schedule I of the Customs Tariff Act;

(v) The Authority forwarded copy of the said public notice to the known exporters, importers and to the complainants and gave them an opportunity to make their views known in writing;

(vi) According to sub-rule (3) of Rule 6 supra, the Authority provided a copy of the petition to all the known exporters and Embassy of subject country in India;

vii) Request was made to the Central Board of Excise and Customs (CBEC) to arrange details of imports of subject goods;

viii) The Embassy of the subject country was informed about the initiation of the investigation in accordance with Rule 6(2) with a request to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time. A copy of the letter, petition and questionnaire sent to the exporters was also sent to them;

ix) A questionnaire was sent to the known importers/users (as per details in the preliminary findings) of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4);

x) Additional information regarding injury was sought from the petitioners, which was also furnished;

xi) Some of the interested parties requested for extension in time to file their response to the questionnaire which was granted upon due cause shown;

(xii) The Authority notified preliminary findings vide notification dated 17th January, 2003 and requested the interested parties to make their views known in writing within forty days from the date of its publication;

(xiii) The Authority also forwarded a copy of the preliminary findings to the Embassy of subject country in India with a request that the exporters/ producers of subject goods and other interested parties may be advised to furnish their views on the preliminary findings in the time frame as stipulated above;

(xiv) The Authority forwarded a copy of the preliminary findings to all the known exporters (whose details were made available by the Petitioner) other exporters who responded to the initiation notification, importers in India and they were requested to furnish their views, if any, on the preliminary findings within forty days from the date of the letter;

(xv) The Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 23rd April, 2003. All parties presenting views were requested to file written submissions of their views expressed. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and offer rebuttals, if any;

(xvi) The Authority made available to all interested parties the public file containing non-confidential version of evidence submitted by various interested parties for inspection, upon request as per Rule 6(7);

(xvii) Arguments made by the interested parties before announcing the preliminary findings, which have been brought out in the preliminary findings notified have not been repeated herein for sake of brevity. However, the arguments raised by the interested parties subsequently have been appropriately dealt in the disclosure statement and these findings;

(xviii) In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties on 8th August, 2003 vide a disclosure statement and comments received on the same have also been duly considered in these findings;

(xix) Cost investigations including spot verification (as deemed necessary) of the domestic industry were also conducted to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and the information furnished by the Petitioner.

(xx) *** in this notification represents information furnished by the interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules;

(xxi) The investigation covered the period from 1st April, 2001 to 31st March, 2002.

(xxii) Copies of the Initiation Notice and Preliminary Findings were also sent to FICCI, CII, ASSOCHAM etc. for wider circulation.

B. VIEWS OF PETITIONERS, EXPORTERS, IMPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES AND EXAMINATION BY AUTHORITY.

3. The views expressed by various interested parties have been discussed in the preliminary findings and also in the disclosure statement. The views which have not been discussed earlier in the preliminary findings and disclosure statement and those now raised in response to the disclosure statement are discussed in the relevant paragraphs herein below to the extent these are relevant as per rules and have a bearing upon the case. The arguments raised

by the interested parties have been examined, considered and, wherever appropriate, dealt in the relevant paragraphs herein below.

4. At the Preliminary Findings stage responses had been received from the following:

Exporters: -

- (i) M/s Nanjing Longyan Chemical Co. Ltd., CHINA
- (ii) M/s Nanjing Jingmei Chemical Co. Ltd., CHINA

Importers

- (i) M/s Nandolia Organic Chemicals Pvt. Ltd., Mumbai
- (ii) Universal Chemicals & Industries Ltd., Mumbai
- (iii) Black Rose Exports Pvt. Ltd., Mumbai
- (iv) Global Bulk Drugs & Fine Chemicals Pvt. Ltd., Hyderabad
- (v) Anant Fragrance Pvt. Ltd.
- (vi) Moraya Global Pvt. Ltd., Mumbai
- (vii) Zenith Enterprises, Ahmedabad
- (viii) Naiknavare Chemicals Ltd., Mumbai

The submissions made by various interested parties had been dealt with in the preliminary findings and these are not being repeated here for the sake of brevity. Subsequent to the public hearing and Disclosures, arguments have been made by the following importers only which have been dealt with appropriately in these findings :

- (i) M/s Blackrose Exports Pvt. Ltd.,
- (ii) Metrochem Industries Ltd.,
- (iii) Nandolia Organic Chemicals Pvt. Ltd.,
- (iv) Universal Chemical Industries Ltd., and
- (v) Inventaa Chemicals Limited.
- (vi) Para Cresol Consumers Association, Mumbai.

5. Product under Consideration :

The product under consideration in this investigation is Para Cresol. The product finds major uses in Dyes and pigments; perfumery and drug intermediates, optical brightener, surfactants, synthetic food flavour, ultra violet light absorbers, anti-oxidants and stabilizers for lubricants.

It has been argued by one of the importers that Para Cresol of 99% plus purity is not offered in the market by the petitioner. Therefore, Para Cresol of 99% purity is required to be excluded from the scope of the present petition. The domestic industry in their written submissions have confirmed that they manufacture all grades of Para Cresol covering purity up to 99%. Further, Para Cresol of 99%

plus purity is not offered in the market: In response to the Disclosures, the importers have argued that the petitioner has admitted that they do not offer 99% purity Para Cresol. This does not seem to be the case as the domestic industry in their written submissions subsequent to the public hearing had confirmed that they manufacture all grades of Para Cresol covering the purity up to 99%. Thus the arguments of the importer do not appear to be correct. The Authority is of the view that the arguments made as regards exclusion of Para Cresol of 99% purity from the scope of the investigation are not cogent and supported with sufficient justification. The Authority confirms the preliminary findings on product under consideration.

6. Like Article

The petitioner had claimed that there is no difference between the products manufactured by the domestic industry in India and the imported products. For the preliminary determination the Authority held that Para Cresol being produced by the domestic industry is like article to the product under consideration. There are no significant arguments on the issue of Like Article subsequent to the preliminary findings. The Authority therefore confirms the preliminary findings as regards Like Article.

7. Domestic Industry

The Authority recalls the preliminary findings on the issue of domestic industry. The petition has been filed by M/s Atul Limited (Aromatics Division), Dist. Valsad, Gujarat. The petitioner company is the sole producer of Para Cresol in India. Therefore, they claim to represent the 100% domestic production of the subject goods. The petitioner had informed in the petition regarding imports of 32 MT of Para Cresol made during POI under Advance Licence for fulfilling export obligation. It has been argued by some of the importers that since the petitioner has made imports during the POI they may not be treated as part of the eligible domestic industry. The Authority had noted that the imports of 32 MT made by M/s Atul Limited during POI were meant for export production and these imports were necessitated due to a planned stoppage of their Para Cresol plant. The Authority did not consider these small quantity imports for export production to make the petitioner as ineligible to be treated as 'Domestic Industry' within the meaning of Rule 2(b) supra. The petitioner was, therefore, considered to represent the domestic industry.

Arguments have been made on behalf of importers viz. M/s Blackrose Exports Pvt. Ltd., Metrochem Industries Ltd., Nandolia Organic Chemicals Pvt. Ltd. and Universal Chemical Industries Ltd. stating that the petitioner lacks the standing to file the petition as they have made imports of subject goods. Further, it has been argued that the following three reasons considered by the Authority while treating M/s Atul Limited as domestic industry are not sufficient :

- (i) Imports made by the petitioner are insignificant,
- (ii) Imports made under advance licence,
- (iii) Imports have been made at a time of temporary shut down of production facilities.

It has been argued that imports made by the petitioner constituted more than 5% of imports whereas under WTO rules, 3% volume of imports is a quantity considered as significant. Further, these imports made by the petitioner were more than 1% of demand of the product. With regard to second reason regarding imports made by the petitioner under advance licence, it has been argued by the importers that it is the practice of the Designated Authority to exclude all such producers from the eligible domestic industry. It has been argued that in the case of imports of Metronidazole from China, three producers were excluded from the purview of domestic industry even though these companies made imports under advance licence. As regards the third reason given by petitioner to have made imports under advance licence in the condition of temporary shut down, it has been argued by the importer that the reasoning defies all logic as at one place, domestic industry claimed that imports were necessitated due to its own requirement for exports and at the same time, it has been stated that imports had to be made due to temporary shut down of the plant. In response to the Disclosures, the importers have reiterated their above stand.

* The domestic industry has drawn attention to the legal position on definition of domestic industry as per Rule 2 (b). They have argued that the word 'shall' existing in the said Rule was amended to read as 'may' by virtue of the Amendment No. 44/99-CUS dated 15.7.1999. Thus specific discretionary powers were vested in the Designated Authority to decide whether in a particular case, the importing domestic industry may be considered not forming a part of the domestic industry under Rule 2(b). In the instant case, the Designated Authority was satisfied that the petitioner should be considered as the eligible domestic industry despite the fact that they have imported the said product. Imports in the instant case were made by the petitioner against advance licence which are totally exempt from the incidence of custom duty and also the anti dumping duty. This exemption is based on the fact that such imports do not enter in the mainstream commerce of the country. Exclusion of producers who imported the product under consideration has to be decided by the Designated Authority on a case by case basis, on reasonable and equitable ground, and by taking into consideration all the legal and economic aspects involved. The purpose of the provisions on the exclusion of certain producers is to obtain an objective and undistorted view of the effects of the dumped imports. It is pertinent to note that the present petitioner has not in any way participated in dumping practices or shielded from its effects or in any way benefited unduly from them. The contention of the importers that the importing domestic industry is ordinarily to be excluded, is not borne out either from a plain reading of the law or from the jurisprudence on the subject. The petitioner has also cited the excerpts from the

book titled "EC Anti Dumping Law, A Commentary on Regulation 384/96 by Nicholas Khan" which contains the practices followed by EC in this regard.

It has been further argued by the petitioner that the preliminary findings on the issue of 'domestic industry' have been misinterpreted and distorted in the submissions made by the importers. The said findings make it amply clear that the imports by the domestic industry have been ignored for determining the standing of the domestic industry because the imports were necessitated to fulfill the export commitments and not for the reasons cited in the submissions of importers / consumers. The reasons in support of questioning the decision of the Designated Authority are based on an erroneous interpretation of the preliminary findings and hence needs to be rejected ab initio. The criteria of 3% volume of imports mentioned by importers has no connection or linkage with the status of the domestic industry to file a petition. The reliance placed by the importers on the Phenol case is also totally mischievous and misleading.

The Authority has examined the arguments made by the importers on the preliminary findings on the issue of 'domestic industry' and the arguments made by the petitioner. The Authority is of the view that Rule 2(b) gives the discretion to the Authority in determining as to whether a domestic producer who has made imports of subject goods can be considered as part of the domestic industry or to be excluded. In the instant case, the petitioner, who is the sole producer of the subject goods in India, had made imports of 32 MT during the POI. These imports were made for export production and these had been necessitated due to a planned stoppage of their Para Cresol plant. The Authority has not considered these imports as very significant, particularly, when these were meant for export production. The reference to the criteria of 3% volume of imports in the context of the determination of standing of domestic industry has no relevance, as these provisions relate to determination of de minimus volume of imports. The facts and circumstances of other cases cited by the importers in support of their arguments are different from the instant case. The Authority therefore, reiterates and confirms its preliminary findings on the issue of 'domestic industry'.

8. Accuracy and Adequacy of Information based on Secondary Sources

The importers have argued that the petition does not contain any reasoning for not relying on DGCI&S data. At the time of initiation of investigation, the DGCI&S had published its data for the POI. There are imports from other countries which are more than the limits prescribed and the prices are significantly lower.

It has been argued by the petitioner in their rejoinder that as mentioned in the petition, the DGCI&S data for Para Cresol (Code 2907 1201) could not be relied upon as the same is not available transaction-wise with detailed description. The petition has further stated that while scanning the IBIS import data for Para Cresol, it was noticed in several instances that other types of

Cresols were classified in the code meant for Para Cresol, which completely distorted the import statistics. Since DGCI&S data did not give transaction-wise details of Cresols imported with appropriate description, it was not feasible for the domestic industry to derive the figures for Para Cresol imports by relying on DGCI&S data. Hence they relied on IBIS data which is based on the customs daily list of some of the major ports. The DGCI&S data submitted by importers indicates that imports are taking place from many countries of European Union. However, the fact is that there is only one producer of subject goods in the entire European Union as would be obvious from the Initiation Notice issued by the EC (2002/C150/04) against imports from China. Thus the DGCI&S data could not be relied on this ground also.

The importers have reiterated their arguments on this issue in response to the Disclosures.

The Authority has examined the arguments made by the importer as regards the petition being made on the basis of secondary source data instead of DGCI&S data. This aspect had also been looked into by the Authority at the time of initiation. It had been explained by the petitioner that the DGCI&S data under Head 2907 1201 contained other types of Cresols also. It had been stated in the petition that the HS Code under the Customs Tariff Act at the six digit level (sub-heading 2907.12) is for all types of Cresols and there is no dedicated code separately for Para Cresols. However, the ITC HS classification and DGCI&S have a separate code only at the eight digit level (2907 1201). Therefore, Meta Cresol, Para Meta Cresol and Mixed Cresols are also getting classified under ITC HS 2907 1201. While compiling the information, there are several instances where other types of Cresols have also got classified along with the Para Cresols under Code 2907 1201 even under the IBIS data. This has also been verified by the Authority. It has also been stated in the petition that since the DGCI&S data does not give the detailed transaction-wise description of the Cresols imported, it is not feasible for the domestic industry to segregate the different types of Cresols for the purpose of anti dumping investigation from DGCI&S statistics. It has also been stated in the petition that India imports Meta Cresols and Meta Para Cresols from other countries than China. Major exporters of these cresols to India are South Africa, Japan, Germany and USA. These imports of Meta Cresols and Meta Para Cresols are for other end uses / applications and therefore, do not conflict with the interest of the domestic industry. The importers have also not produced any cogent evidence showing imports of Para Cresol from other countries in the form of transaction-wise imports giving description of import products. In the circumstances, the Authority has relied upon the import evidence based on secondary sources as furnished by the petitioner.

9. Grossly Deficient Non-Confidential Petition

It has been argued by the importer that the Non-Confidential Petition does not permit reasonable understanding of the substance of information contained in

the Confidential Petition. Almost all data has been claimed confidential which is unjustified and unsupported with the rules. The importer had sought all information on index basis.

The petitioners have argued that the questionnaire response filed by the importer are highly inadequate, selective and lacking in substance. Specifically, M/s Nandolia and M/s Universal Chemicals & Industries Ltd. have not given any non-confidential version on the pretext that the information is sensitive. These parties may be compelled to submit their proper responses before their submissions are taken cognizance of. As regards petitioner's non-confidential version, they have stated to have given the non-confidential version including the indexed information to the extent the confidential information was amenable to summarization / indexation.

The Authority has examined the arguments. The petitioner had given non-confidential version that contained information regarding imports. Indexed information regarding total demand, market share of petitioner, production and capacity utilization, sales volume, sales value and unit price has also been given. The petitioner had also shared their annual report by placing in the public file. The Authority is of the view that in accordance with Rule 7(1), the information claimed as confidential by the petitioner may be treated as confidential and to the extent feasible, the petitioner has provided non-confidential summary as per Rule 7(2).

C. EXAMINATION OF CLAIMS REGARDING NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN.

10. The Authority recalls preliminary findings regarding determination of Normal Value, export price and dumping margin. At the preliminary findings stage, responses were received from the following two exporters:

- (i) M/s Nanjing Longyan Chemical Co. Ltd., CHINA
- (ii) M/s Nanjing Jingmei Chemical Co. Ltd., CHINA

The Authority had noted that the two exporters had claimed market economy / individual treatment on the ground that they independently operate production and business activities, freely select suppliers and customers and develop sales market in response to the signal of the market. The Authority had, however, found that sufficient evidence and information on the basis of the criteria specified in sub-para (3) in paragraph 8 had not been furnished to rebut the presumption that the exporters are from non-market economy. The Authority was, therefore, unable to apply the principles set out in paragraph 1 to 6 of Annexure 1 of Rules supra and was constrained to proceed as per 'facts available'. In addition, the Authority observed that the information furnished by the exporters relating to cost of production as required under Appendix 8 & 9 of the questionnaire was incomplete and incorrect. In respect of raw materials, the

ratio of each raw material in the final product was not given; the basis of allocation of costs to Para Cresol production was not given. From the available financial statement viz. profit & loss account, balance sheet, the cost of production for the POI was not verifiable. As the furnished information did not enable the Authority to verify the cost of production, the domestic sales transaction could not be treated to be in the ordinary course of trade. The Authority had separately informed in detail through letter dated 17th January, 2003, the shortcomings in the information furnished to the concerned exporters.

Therefore, under the circumstances, Normal value under the Rules was provisionally determined on the basis of 'facts available' as per Rule 6(8). Thus, the information available on the estimated cost of production as per evidence furnished by the petitioner plus selling, administrative and general expenses and a reasonable amount of profit had been taken as the basis for working out the Normal value of subject goods in China PR. While considering the evidence regarding cost of production furnished by the domestic industry, the Authority had referenced the Normal Value with reference to actual cost of production of domestic industry after normating it at optimum efficiency level.

Subsequent to the Preliminary Findings, there has been no response from any exporter either on the preliminary findings or after the holding of public hearing or on the Disclosure Statement. The Authority therefore, confirms preliminary findings as regards Normal Value, export price and dumping margin.

Dumping Margin :

11. The Authority followed the consistent practice of adopting the principles governing the determination of Normal Value, Export Price and Margin of Dumping as laid down in Annexure I to the anti-dumping rules. Dumping margins have been determined on the basis of a fair comparison of Export Price with the Normal Value in pursuance of the principle laid down in Para 6 of Annexure-1 to the Rules. The comparison is at the same level of trade, i.e. Ex-factory level. Based on the Normal Value and export price as determined above, the Authority confirms to adopt the following dumping margins(%):

| S. No. | Name of Exporter | Dumping Margin % |
|--------|---|------------------|
| 1. | M/s Nanjing Jingmei Chemical Co. Ltd. , CHINA | 40.74% |
| 2. | M/s Nanjing Longyan Chemical Co. Ltd., CHINA | 31.94% |
| 3. | Other Exporters from China P.R. | 45.04% |

D. INJURY AND THREAT OF INJURY

12. Rule 11 of Anti Dumping Rules reads as follows:
"Determination of Injury:

(1) In the case of imports from specified countries, the designated authority shall record a further finding that import of such article into India causes or threatens material injury to any established industry or materially retards the establishment of any industry in India;

(2) The designated authority shall determine the injury to domestic industry, threat of injury to domestic industry, material retardation to establishment of domestic industry and a causal link between dumped imports and injury, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on price in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles and in accordance with the principles set out in Annexure II to these rules."

13. The principles for determination of injury set out in Annexure-II of the Anti-Dumping Rules lay down that:

a. A determination of injury shall involve an objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for like article and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products.

b. While examining the volume of dumped imports, the said Authority shall consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of Rule 18 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price under-cutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree.

14. **Views of the Importer**

- (i) As regards imports, the product is classified in dedicated Customs sub-heading, yet the DGCI&S data has been ignored. There is increase in imports. However, the same was largely due to commencement of production of PAA by three companies. Since petitioner does not cater to this requirement, these imports cannot cause injury.

- (ii) As per indexed figures of production in the petition, there was an increase whereas elsewhere in the petition, it was stated the production of domestic industry declined.
- (iii) The producers of downstream products are the consumers of Para Cresol. To get them out of business, the domestic industry has filed the petition.
- (iv) Sales volumes have increased significantly. Thus decline in market share or capacity utilization cannot be linked to imports. Captive consumption of domestic industry has declined and the same cannot be a ground to seek imposition of anti dumping duty on imports. It is admitted in the Annual Report of petitioner that the competition with the user industry is the reason of drop in prices.
- (v) Even if selling price has declined in a situation of increase in export price as well as landed value, the same cannot be attributed to alleged dumped imports.
- (vi) Selling price (net of excise) of the domestic industry has increased as is evident from the Annual Report of the Company. Cost of production has declined in POI. Increase in selling price should have resulted into increase in profitability of the domestic industry.
- (vii) There is contradiction in the figures as production increase, sales increase and stocks have also shown to have increased.
- (viii) There is significant gap between demand and supply of the material. Therefore, even after imposition of anti dumping duty, consumers will have no option but to import the material.
- (ix) Since landed price of imports from China is higher than the selling price of domestic industry, the imports could not have caused injury or do not threaten material injury to the domestic industry. In this regard, final findings notified recently by the Designated Authority in the matter of NTCF are referred wherein Authority has held that there is no causal link between the dumped imports and material injury to the domestic industry due to the existence of the negative price under cutting.
- (x) Price under selling cannot be a reason of alleged injury due to dumping. It is not understood how imports resulted in price under selling in the market.
- (xi) There are imports from other countries at comparable or lower prices, hence causal link is not established.

- (xii) The increased imports are on account of imports made by producers of PAA, who have come in existence very recently and to whom the domestic industry is not selling its material at all. Therefore, imports made by these consumers cannot cause injury to the domestic industry.

Para Cresol Consumers Association has made following arguments in response to the Disclosures :

- (i) Petitioner does not supply material to PAA producers. Petitioner has attempted to create all hurdles in smooth commercial production of PAA with a view to eliminate other producers.
- (ii) As per petitioner's own admission, they do not quote for supply of Para Cresol with 99% purity.
- (iii) Imports include Para Cresol of 99%. These are required to be removed while examining increase in imports as the petitioner does not supply this material nor are they keen in supplying this material.
- (iv) The petitioner intends to expand the capacity to meet the demand. There is fallacy in the argument as the petitioner is (a) claiming unutilized capacity, (b) regretting supply of Para Cresol 99% purity and (c) increase in sales volume and yet claiming expansion of capacity.

15. Views of the Domestic Industry

In response to the comments of the importers, the domestic industry has made following arguments :

a) Domestic Industry's capacity to cater to demand

It has already been clarified that the capacity of the petitioner to manufacture Para Cresol is 5500 MT which is adequate to meet the demand of Para Cresol. The domestic industry is also planning to increase its capacity to 10,000 MT in order to cater to the increasing demand.

b) Misleading and Incorrect Statements by the Importer

Importers have given patently incorrect statement with regard to the non-confidential version of the application and the preliminary findings. It has been mentioned by the importers that the preliminary findings indicate an increase in capacity utilization whereas the fact is that in para 29 of the preliminary findings, the Designated Authority has recorded its findings that the capacity utilization has gone down. It is obvious that all the arguments based on this false premise

of increase in capacity utilization during the POI cannot be sustained. The statement of the importer regarding contradiction in the production figures given in page 9 and 14 of the Petition is also incorrect and misleading. The domestic industry has clearly indicated on page 14 that the production has declined during the POI over the preceding year which is in line with the statement made at page 9.

c) Selling Prices

The importers had argued that the selling prices have increased during the POI. This contention is reportedly based on the Balance sheet of the domestic industry. The non-confidential version of the application clearly shows that the selling prices have drastically declined during the POI over the previous financial year.

d) Price Underselling / Price Undercutting and Injury to Domestic Industry

The importers have submitted that since landed price of imports is higher than the selling price of the domestic industry, the imports could not have caused injury or do not threaten material injury to the domestic industry. In this connection, the importers have drawn reference to the view taken by Designated Authority in the case of NTCF where it was held that there is no causal link between the dumped imports and material injury to the domestic industry due to existence of negative price under cutting. The case of NTCF relates to review and not for a fresh investigation. The reliance placed by the respondent is wholly misplaced as the criteria to be adopted for review under Rule 23 are entirely different from the parameters laid down under Annexure II of the Anti Dumping Rules. The said Rules require that the impact of volume of imports be assessed in terms of price under cutting or price suppression or price depression. Therefore, the contention that in the absence of price under cutting, imports could not have caused injury or do not threaten material injury to the domestic industry is not borne out from the provisions of law.

As decided by the Designated Authority in the preliminary findings, we hold that the most significant cause of injury to the domestic industry has been the price under selling. As a result of lower landed value of imports of subject goods from subject country, the domestic industry has not been able to realize a fair and reasonable price for its products resulting into severe price depression. This has led to negative return on investment. The investment in the Para Cresol manufacturing industry are quite high and the loss on sales realization has resulted in losses and negative return on investment by the industry which reflects the injury suffered. The Designated Authority has given affirmative findings on injury on the basis of price suppression in several cases.

Examination by the Authority

16. The Authority has examined the following injury parameters for making final determination;

Imports, market share of domestic industry, imports from subject country, changes in market share, production, capacity utilization, sales volume and value, net sales realization, inventories, employment, wages, profitability, return on investment, magnitude of margin of dumping etc.

17. The Authority has also examined various arguments made by the petitioner and the importers/exporters on injury. The Authority does not find the contention of the importer as correct regarding any contradiction in the production figures mentioned on pages 9 & 14 of the Petition. Similarly, the Authority finds the claim of the importer regarding increase in capacity utilization as incorrect. The Authority had found the following status of capacity utilization in the preliminary findings under para 29:

"The Authority finds that the capacity utilization of the domestic industry declined during the POI as reflected in the table below:

| Year | Capacity Utilization (%) |
|-----------------|--------------------------|
| 1999-2000 | 61.78% |
| 2000-2001 | 67.71% |
| 2001-2002 (POI) | 62.80% |

(Indexed)"

18. As regards selling price, the Authority notes from the Annual Report of the Company for the year 2001-2002, the performance of Aromatic Division shows that *"supply being well in excess of demand and aggressive marketing by the competitors affected the price structure significantly. The Division has to drop prices substantially in order to hold on to the market share."* The Authority has also verified the net sales realization of the domestic industry and has found that the same has declined significantly during the POI in comparison to the previous year.

Imports from subject country :

19. As per the petition, the imports from subject country were 267.4 MT in 1999-2000, 724 MT in 2000-01 and 586 MT during POI 2001-02. However, as per the information received from the exporters / importers, the Authority finds that the imports of Para Cresol from subject country during POI were 1217.88 MT. The Authority finds that imports from subject country grew by 68% during POI over the previous year. However the share of imports from subject country in the total imports grew to 100% during POI in comparison to the previous year share of 99.72% and in the year 1999-2000 of 68.82%. The Authority finds that

there has been significant increase in the dumped imports from subject country in absolute terms.

Market share:

20. The Authority finds that the market share of the domestic industry and the imports from the subject country in the demand of subject goods has been as under :

| | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002(POI) |
|---------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| Share of domestic industry (%) | 49.67% | 27.68% | 30% |
| Share of imports from subject country | 34.54% | 72% | 70% |

Market share of imports from subject country in the total demand for the subject goods has increased from 34.54% in 1999-2000 to 70% during POI. However, the market share has reduced from 72% in the previous year. The market share of the domestic industry in the total demand of subject goods has not declined during POI. It has increased from 27.68% during 2000-01 to 30% during the POI.

Capacity Utilisation:

21. The Authority finds that the capacity utilization of the domestic industry declined during the POI as reflected in the table below:

| Year | Capacity Utilization (%) |
|-----------------|--------------------------|
| 1999-2000 | 61.78% |
| 2000-2001 | 67.71% |
| 2001-2002 (POI) | 62.80% |

(Indexed)

Sales Volume :

22. Sales volumes of domestic industry increased from ** in 2000-01 to *** in POI and indexed figures are as under :

| Year | Sales Volume (MT) |
|-----------------|-------------------|
| 1999-2000 | 100 |
| 2000-2001 | 69 |
| 2001-2002 (POI) | 130 |

Inventory :

23. The Authority finds that the inventory of finished goods held by the domestic industry has increased considerably at the end of financial year in March, 2002 in comparison to the previous year closing on March, 2001. This showed an increase of ***%.

Employment :

24. The employment has marginally decreased in the period of investigation.

Wages :

25. The Authority notes that the wage costs have gone up.

Profitability:

26. The Authority has taken note of the arguments of some of the importers/ users that Aromatic Division of M/s Atul Limited makes huge profits and therefore, domestic industry cannot claim injury. M/s Atul Limited manufactures several products in the Aromatic Division and Para Cresol is one of the products. The Authority finds that dumping of subject goods had a significant impact on the net sales realization of the domestic industry for the subject goods. The petitioner had to compete with the low priced offers / imports of subject goods from subject country. The cost of sales has been higher than the sales realization resulting in losses suffered by the domestic industry in the manufacture and sale of subject goods during POI. Therefore, the Authority finds that the domestic industry has suffered losses in their manufacturing operation relating to Para Cresol.

Return on capital employed:

27. The Authority notes that manufacturing of Para Cresol is highly capital intensive. Instead of earning a reasonable profit, the domestic industry, is in fact incurring a loss of Rs.*** per MT on the sales of Para Cresol. Therefore, the domestic industry is incurring a loss of ***% on effective capital employed on per MT production of Para Cresol.

Price under selling:

28. The Authority has compared the Non-injurious price of the domestic industry with the landed value of imports of subject goods and has found that there is significant price under selling as a result of dumped imports.

| | |
|-----------------|----------|
| NIP | *** |
| Landed value | *** |
| Under selling % | ***(+ve) |

Actual and potential negative effect on cash flows:

29. The Authority finds that the domestic industry has not been able to earn even nominal returns on the capital employed for manufacture of Para Cresol. The inventory levels are also high. Therefore, there is a considerable impact on the cash flows of the domestic industry.

Growth:

30. The Authority notes that the domestic industry is planning expansion to cater to increasing demand.

31. Conclusion on Injury :

- i) There has been an increase in imports of subject goods from subject country in absolute terms.
- ii) The market share of the dumped imports from the subject country has increased significantly during POI in comparison to the year 1999-2000. However, it has decreased marginally during the POI in comparison to the previous year.
- iii) The selling price of the domestic industry decreased during the POI as compared to year 2000-01 and the same has been below the non-injurious price (NIP) on account of dumped imports.
- iv) The domestic industry has suffered injury due to price suppression. They have not been able to raise their selling price so as to realize a fair return on the investments as the landed value of the dumped imports has considerably depressed the selling price of the domestic industry.
- v) The Authority concludes that the most significant cause of injury to the domestic industry has been the price under selling. As a result of lower landed value of imports of subject goods from subject country, the domestic industry has not been able to realize a fair and reasonable price for its products. This has led to negative return on investment. The investments in the Para Cresol Manufacturing Industry are quite heavy and the loss on sales realization has resulted in losses and negative return on the investment by the industry which reflects the injury suffered by the industry.
- vi) The above economic parameters cumulatively and collectively establish that domestic industry has suffered material injury.

E. CAUSAL LINK

32. The Authority has examined the impact of the dumped imports on the domestic industry as per principle (v) of Annexure-II of the Anti-Dumping Rules. The relevant indices as set forth in para (iv) of Annexure II of the Rules have been examined by the Authority.

33. The Authority has considered the views expressed by the petitioners and other interested parties as regards the causal link, which have been mentioned, in the preceding paragraphs. The Authority finds that there is significant price under selling as a result of the dumped imports from subject country. As a result of lower landed value of imports of subject goods from subject country, the domestic industry has not been able to realize a fair and reasonable price for its products. This has led to very marginal return on investment. The investments in the Para Cresol production are quite heavy and the low return achieved on the investment by the industry reflects the injury suffered by the industry. The demand of the subject goods has not decreased but has instead increased and therefore, contraction of demand cannot be attributed as a cause of injury. The Authority also notes that the domestic industry is globally competitive and changes in technology or competition amongst the domestic producers do not appear to be the cause of injury. No technological development in the industry or any other such factor which could have resulted in injury to the domestic industry has been noticed.

34. While determining the non-injurious price for the like articles for the domestic industry, the Authority has used the actual cost of production of the subject goods to determine optimum cost of production for the domestic industry which would take into account the normated best consumption norms and the actual price of the raw materials which are consumed for the production of the subject goods during the period of investigation.

F. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST

35. The purpose of anti dumping duties in general is to eliminate dumping which is causing injury to the domestic industry and to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market which is in the general interest of the country.

36. The Authority recognizes that the imposition of anti dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition on the Indian market will not be reduced by the anti dumping measures. On the contrary, imposition of anti dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. The Authority notes that the

imposition of anti dumping measures would not restrict imports from subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

G. CONCLUSIONS

37. The Authority has, after considering the foregoing, come to the conclusion that:

- (i) Para Cresol has been exported to India from subject country below the normal value;
- (ii) The domestic industry has suffered material injury;
- (iii) The material injury has been caused cumulatively by the dumped imports of subject goods from subject country;

38. It is considered necessary to impose definitive anti-dumping duty on the imports of subject goods. Accordingly, the Authority recommends imposition of anti dumping duty on the imports of Para Cresol from subject country.

39. It is decided to recommend the amount of anti-dumping duty equal to the margin of dumping or less, which if levied, would remove the injury to the domestic industry. The landed price of imports was also compared with the non-injurious price of the domestic industry, determined for the period of investigation. Accordingly, it is proposed that definitive anti-dumping duties be imposed on Para Cresol originating in or exported from the subject country being cleared under Heading 2907.12 of the Schedule I of Customs Tariff Act. The anti-dumping duty shall be the difference between the amount mentioned in Col. 9 of the Table below and the landed value of imports of subject goods in US\$ per MT.

| S.No | Sub-Headin g | Description of Goods | Specification | Country of Origin | Country of Export | Producer | Exporter | Amount | Unit of Meas urem ent | Currenc y |
|------|-----------------|-------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 2907.12 | Para Cresol | -- | Any country | China | Any producer | Any exporter | 2220.95 | MT | US\$ |
| 2. | 2907.12 | Para Cresol | -- | China | Any country | Any producer | Any exporter | 2220.95 | MT | US\$ |

40. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

41. Subject to the above, the Authority confirms the preliminary findings dated 17th January, 2003.

42. An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act, *supra*.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority